सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन

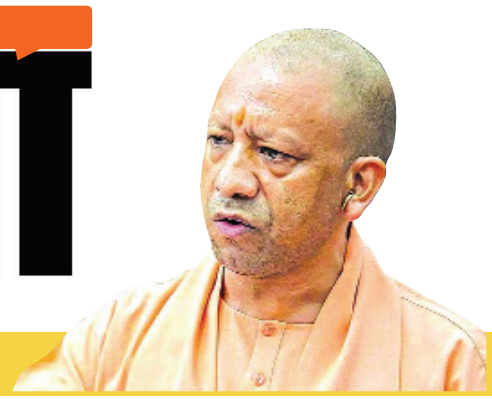

ट्रंप और मस्क की दोस्ती जंग में तब्दील

कानपुर,शनिवार , 07 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 159, पृष्ठः 8+4

इनसाइड हर्षोल्लास व अकीदत से मनाया गया ईद-उल-अज़हा » Pg10

» Pg12

डीजीपी का पद संभालते ही एक्शन मोड में राजीव कृष्ण

» कड़ी समीक्षा बैठक में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 10 मुख्य पॉइंट पर निर्देश दिए हैं

» थाना प्रभारियों की पोस्टिंग में मेरिट को ध्यान में रखने की बात कही है।

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कानून- व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर राजीव कृष्ण ने जरूरी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शुक्रवार को प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 10 प्रमुख प्राथमिकताओं के तहत दिशा-निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान राजीव कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता प्रोफेशनल पुलिसिंग, जनता में विश्वास और अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बैठक के दौरान बताया कि पिछले 8 सालों में ष्टरू योगी की मजबूत इच्छाशक्ति से यूपी ने देश और दुनिया में कानून-व्यवस्था का एक नया मानक स्थापित किया है। अब इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। साथ ही कहा कि थाना प्रभारियों की पोस्टिंग सिर्फ मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। डीजीपी को सीएम योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा माना जा रहा है। ऐसे में सरकार की कानून व्यवस्था

के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति को बढ़ाने में इनका जोर दिख रहा है।

पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने बैठक में कहा कि पुलिसिंग जनता और फोर्स के बीच में एक विश्वास के रूप में कायम रहती है और हमें एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण अपनाते हुए इंटरनेशनल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अपनी कार्यशैली में समावेश करना। उन्होंने कहा कि दृढ इच्छाशक्ति के बहुत दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं और उनसे एक व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। दृढ इच्छाशक्ति से आधी लड़ाई अपने आप जीती जा सकती है।

राहुल का वार, चुनाव आयोग का इमोशनल पलटवार

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर ट्वीट किया था महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो कानून का अपमान है

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए एक ट्वीट से नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने तगड़ा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह कानून का सीधा अपमान है।

चुनाव आयोग ने बताया कि उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जवाब दिया गया था। वह जवाब ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है। ईसीआई का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन तथ्यों को बार-बार अनदेखा किया जा रहा है और फिर से वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

हमलोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं- चुनाव आयोग

ईसीआई ने आगे कहा कि किसी के द्वारा भी फैलाई जा रही कोई भी गलत जानकारी न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि यह अपनी ही राजनीतिक पार्टी द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद, चुनाव आयोग को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश करना कि यह समझौता किया गया है, पूरी तरह से बेतुका है। इसका मतलब है कि हारने के बाद ईसीआई पर आरोप लगाना गलत है। ईसीआई के कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं और उन पर शक करना ठीक नहीं है। ईसीआई का कहना है कि चुनाव में हारने के बाद कुछ लोग ईसीआई पर गलत आरोप लगाते हैं। यह गलत है और इससे ईसीआई की छवि खराब होती है। ईसीआई ने सभी आरोपों का जवाब पहले ही दे दिया है और उसे वेबसाइट पर भी डाल दिया है।

खासपुर गांव की गरमाई सियासी जमीन

» गांव पहुंच मंत्री आशीष पटेल

ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बोले किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं

कहा कि समस्या होने पर उन्हें बताएं वह तुरंत आयेंगे

खासपुर गांव पहुंच लोगों को समझाया बुझाया

पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह को दिए सख्त दिशा निर्देश

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। सूबे के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री आशीष पटेल ने शनिवार को बिल्हौर के खासपुर गांव में कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग कतई परेशान न हो यदि कोई समस्या होती है तो हमें फोन करें और हम 4 से 6 घंटे के अंदर आपके पास उपस्थित होंगे। उल्लेखनीय है कि बिल्हौर का यह गांव पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है।

यहां के पूर्व प्रधान अशोक कटियार पर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद से राजनीति अचानक गरमा गई थी जिसमें स्थानीय विधायक राहुल बच्चा और सपा की नेत्री रचना सिंह आमने-सामने आ गई थी। गांव में कई पोस्टर लग गए थे कि मकान बिकाऊ है। लोगों के पीछे संदेश गया था कि गांव के लोग डरकर घबराकर गांव से पलायन कर रहे हैं। यह खबर तेजी से आग की तरह फैली और उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया। मामला तूल पकड़ने के बाद शासन ने इसे संज्ञान में लिया और आज सुबह कुर्मी बिरादरी का मामला होने के कारण सजातीय मंत्री आशीष पटेल को यहां पर भेजा गया। उन्होंने बड़े ही आत्मीय ढंग से लोगों के बीच अपनी बात रखी। जिससे लोगों के बीच का आक्रोश कुछ कम हुआ। साथ ही उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव को सख्त निर्देश दिए कि गांव में कम से कम एक सिपाही परमानेंट तैनात किया जाए ताकि किसी प्रकार की छोटी बड़ी घटना की सूचना समय से पुलिस के अधिकारियों तक पहुंच सके। इस दौरान विधायक राहुल बच्चा सोनाकर, जेपी कटियार,रिंकू,जिलाउपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, बबलू कटियार, अंकित, उज्ज्वल समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

विधायक की शिकायत पर हल्का के दरोगा नपे

पूर्व प्रधान अशोक कटियार पर हुए हमले की जाँच में लापरवाही बरतने वाले दरोगा दयाशंकर को उच्च अधिकारियों ने शुक्रवार को लाइन हाजिर कर दिया। बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर की शिकायत पर अधिकारियों ने दरोगा पर यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि गांव वाले दरोगा के व्यवहार से खुश नहीं थे।

चर्चित नेता का नाम लोगों की जुबान पर

सूत्रों के हवाले से जिस नेता के इशारों पर गांव में पलायन के कुछ लोगों ने पोस्टर चस्पा किए थे। स्वराज इंडिया अख़बार में उसका जिक्र होने के बाद शुक्रवार उस चर्चित नेता की काफ़ी चर्चा होती रही। हालांकि पुलिस इशारों ही इशारों में सब कुछ समझ गई है। खुफिया विभाग की भी उस चर्चित नेता पर नजर है। पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी जो मामले को हवा देने में लगे थे।अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का अब पूरा मन बना चुके हैं। अभी उनका टारगेट बाकी आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेजना है।

मुख्य आरोपी रामदीन धरा गया

पुलिस ने बताया है कि हमले का मुख्य आरोपी रामदीन गिरफ्तार कर लिया गया है। एक को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। अब तक मामले में पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अरौल इंस्पेक्टर का कहना है जल्द वह भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

प्राथमिक शिक्षा में अभी भी व्यापक सुधार की जरूरत

कुछ स्कूलों का अच्छा होना पूरे शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात हो तो अक्सर चर्चा केवल कुछ विशेष और सुसज्जित स्कूलों और गिने-चुने उत्कृष्ट शिक्षकों तक सीमित रह जाती है। यह सच है कि कुछ बेहतरीन शिक्षक और शानदार स्कूल एक मिसाल बनते हैं परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि पूरे शिक्षाक्षेत्र की हालत इन थोड़े से उदाहरणों के भरोसे नहीं सुधारी जा सकती। इनकी प्रशंसा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए पर यह भी समझना जरूरी है कि शिक्षा का दायरा अत्यंत विस्तृत है जिसमें केवल कुछ हिस्सों की चमक बाकी हिस्सों के अंधकार को मिटा नहीं सकती। पिछले कुछ वर्षों में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई गईं। इनसे कुछ स्कूलों और शिक्षकों को जरूर आगे बढ़ने का अवसर मिला लेकिन व्यापक सुधार के लिए इन नीतियों का प्रभाव सीमित रहा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बड़े फसल क्षेत्र में केवल कुछ पौधों को पानी और खाद दी जाए और बाकी पौधे सूखे रह जाएं। समग्र फसल के लिए समग्र देखभाल आवश्यक है केवल कुछ पौधों की नहीं। समग्र परिवर्तन के लिए शिक्षा क्षेत्र में सभी स्कूलों और शिक्षकों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यह परिवर्तन छोटे और सीमित दायरे में नहीं बल्कि बड़े और विस्तृत स्तर पर होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत और सक्षम आधार देने के लिए व्यापक स्तर पर नीतिगत बदलावों की जरूरत है। इस संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधनों का उचित वितरण और पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति में सुधार लाना भी अत्यंत आवश्यक है कुल मिलाकर केवल कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करना शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सुधार नहीं ला सकता। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी विद्यालयों और शिक्षकों को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। शिक्षा क्षेत्र में एक व्यापक और विस्तृत सुधार की आवश्यकता है ताकि हर बच्चा एक समान और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सके।

महिला आयोग के अध्यक्ष से मिले मो0 उस्मान अली शाह

महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार व अपराधीकरण के विरोध में की वार्ता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार व अपराधीकरण के विरोध में डॉ0 बबिता सिंह,चौहान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश शासन एवं अनिता गुप्ता सदस्य से मो0 उस्मान अली शाह चेयरमैन राष्ट्रीय मानव अधिकार कार्य0 परिषद ने मुलाकात से की। इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एवं शासन की मंशा को धता बताकर थाने स्तर के कुछ पुलिस अधिकारी महिला उत्पीड़नकारियो के पक्ष धर बन कर उभरे हैं उनकी भाषा भी मर्यादा विहीन है । अभद्रतापूर्ण वार्ता करते हैं। 498,223,125,,व 376 जैसे मुद्दों को भी दर किनार करने की वजह से महिलाओं व उनके परिजनों को पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वार पर भटकना पड़ता हैं, आयोग अपनी कार्यवाही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें ताकि कानून व्यवस्था को व शासन की नीतियों को मजाक उड़ाने वालो के विरुद्ध शक्ति से निपटा जा सके । महिलाओं को अपमानित महसूस होने बचाया जा सके। इस दौरान अजीत कुमार, अम्न कुमार, टोनी सिंह,चन्दन सहित अन्य मौजूद रहे।

प्रवर्तन करना चाहता कार्रवाई, साहब डाल रहे अड़ंगा

» भौंती स्थित फूड कोर्ट के अवैध निर्माण में एक केडीए अफसर की डीलिंग उजागर

» एक वरिष्ठ अफसर की भूमिका संदिग्ध, उपाध्यक्ष को दी गई 8 जानकारी

» अवैध निर्माणों एवं प्लाटिंग में अफसर कर रहे सीधे डीलिंग

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग रोकने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण में गठित प्रवर्तन दस्ता और अफसरों के बीच लुकाछिपी का खेल चल रहा है। शहर में अनाधिकृत निर्माणों के कुछ ऐसे प्रकरण बताए गए हैं जिनमें प्रवर्तन दस्ता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्यों कि केडीए अफसर का 'अभयदान' मिला हुआ है। इससे प्राधिकरण में राजस्व हानि हो रही और छवि पर भी विपरीत असर पड रहा है।

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com कानपुर सिटी कानपुर, गुरुवार 05 जून, 2025 03

केडीए के 'अभयदान' से तन गया अवैध फूड कोर्ट

» वीसी मदन सिंह गर्ब्यांयाल के निर्देशों को दरकिनार कर जारी है अवैध निर्माण

» भ्रष्टाचार की जड़ में अफसरों और बिल्डर की लाखों की सांठगांठ

» अवैध निर्माण पर प्रशासन की चुप्पी, रसूखदार की दबंगई भारी

आज की डेट में जारी निर्माण कार्य

भौतिप्रताप्पुर, उत्तर प्रदेश, भारत
F645+97v, नेशनल हाईवे 19, भौतिप्रताप्पुर, उत्तर प्रदेश 208020, भारत
Lat 26.456004° Long 80.208216°
05/06/2025 11:54 AM GMT +05:30

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। महानगर के भौंती हाईवे किनारे बन रहा दीपू चौहान फूड कोर्ट कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के नियमों और शहरी विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से ताक पर रखकर तैयार हो रहा है। जबकि केडीए के उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल स्वयं मीटिंगों में बार-बार अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के निर्देश दे चुके है, लेकिन उनका आदेश नीचे तक पहुंचते-पहुंचते या तो कमजोर पड़ जाता है या जानबूझकर अनदेखा कर दिया जाता है। निर्माणकर्ता पहले ही जिला पंचायत का नक्शा दिखाकर न्यायालय गया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शहरी सीमा के अंतर्गत ऐसे नक्शों की कोई वैधता नहीं है।

इसके बावजूद निर्माण कार्य दिन-रात जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रात के अंधेरे में भी निर्माण सामग्री लाई जा रही है और श्रमिकों को छुपाकर काम पर लगाया जाता है। इससे यह साफ होता है कि निर्माणकर्ता न केवल अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा है बल्कि कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती भी दे रहा है। हाईटेंशन तारों के ठीक नीचे बन रही इस विशाल इमारत से भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केडीए और जिला प्रशासन इस सब पर चुप्पी साधे बैठा है।

लाखों की डील ने बदल दिया सिस्टम का चेहरा

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, दीपू चौहान फूड कोर्ट से जुड़े इस पूरे निर्माण कार्य में केडीए के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और एक प्रभावशाली इंजीनियर के बीच लाखों रुपये की अवैध डील हुई है। यही वजह है कि पहले जहां इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को पत्र लिखा गया था, वहीं अब सब कुछ शांत है और निर्माण कार्य खुलेआम चल रहा है। अधिकारियों की इस चुप्पी ने पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार किस हद तक केडीए में जड़ें जमा चुका है।

स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि जिस जमीन पर यह फूड कोर्ट बनाया जा रहा है, वह एक सरदार जी के स्वामित्व वाली भूमि थी, जिस पर पुराने टायरों का भंडारण होता था। नक्शे में जितनी जमीन दिखाई गई है, उससे अधिक पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों में भी भारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। कंपाउंडिंग कराने से बचने का कारण भी यही है कि यदि ऐसा किया गया तो जमीन का असली चेहरा उजागर हो जाएगा और निर्माणकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय हो जाएगी। इस पूरे मामले की फाइल अब शासन तक पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भ्रष्ट अफसरों और भू-माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण रोकने के लिए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया है, फूड कोर्ट संचालक ने कोर्ट में दोबारा प्रत्यावेदन दिया है, इसको देखा जा रहा है। डीसीपी को पत्र भेजा जा रहा है और रोक के बाद भी निर्माण न रोकने पर कठोर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
अभय पाण्डेय, सचिव केडीए

अफसर सक्रिय हुए। निर्माण को लेकर केडीए ने नोटिस दिए लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। क्यों कि बताया जा रहा है निर्माणकर्ता के रसूक और पैसे की खनक के आगे नियम-कायदे बौने साबित हो जाते हैं। वैसा ही हो रहा है...केडीए ने निर्माण बंद करने के नोटिस दिए तो निर्माणकर्ता ोर्ट चला गया। कोर्ट ने केडीए को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिए, इधर इसके बाद भी काम नहीं रोका गया। इधर, केडीए सचिव की ओर से प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए निर्माण को अवैध बता दिया गया और कंपाडिंग मैप दाखिल करने को कहा

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com कानपुर सिटी कानपुर, बुधवार 04 मई 2025 07

अवैध निर्माणों की लंबी फेहरिस्त
मालामाल प्रवर्तन दस्ता

काकादेव क्षेत्र में केडीए द्वारा सील परिसर में निर्माण की वायरल फोटो

» जोन-2 के लाजपतनगर, कौशलपुरी, काकादेव, पनकी और कल्याणपुर सहित कई हिस्सों में दनादन अवैध निर्माण

» शहर भर में अवैध प्लाटिंग रोकने के नाम पर हो रही उगाही

» प्रवर्तन कर्मी दिनरात निर्माणकर्ताओं से सिर्फ सेंटिंग करने में जूझते दिखते

खास खबर

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। अवैध निर्माणों को लेकर राज्य सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक सख्त है। इसके बाद भी उनके नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण और प्लाटिंग रोकने के लिए दस्ता गठित लेकिन दस्ता में शामिल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक वसूली, उगाहीकर अपनी जेबें भरने में जुटे हैं। अवैध निर्माण रोकने का दिखावा किया जा रहा है।

बीते दिनों कानपुर के चमनगंज इलाके में बहुमंजिली अवैध इमारत में आग लगने से पांच लोगों की जलकर मौत हो गई थी, यहां पर बिना नक्शे के बेसमेंट सहित कई मंजिल की इमारत खडी कर दी गई थी। केडीए और अन्य विभागों की मिलीभगत से शहर में ऐसी सैकडों इमारतें मौत के कुएं की तरह खडी कर दी गई हैं। जिनमें हर समय हादसे का खतरा मंडरा रहा है। विभाग अनजान बने बैठे हैं। मंगलवार को नगर निगम में आयोजित सदन बैठक में मेयर प्रमिला पांडेय ने ऐसी इमारतों के निर्माण और उनमें चल रहे कारखानों, उद्योगों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होने कहा कि पार्षदगण अपने अपने इलाकों में ऐसी इमारतों में ध्यान दें। वहीं, शहर के आउटर इलाकों की कृषि जमीनों पर बिना लेआउट के दनादन प्लॉटिंग कर अवैध सोसायटियां बसाई जा रही हैं, जिनमें सीवर, पानी और स्वस्थ्य वातावरण का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में ऐसी सोसायटियां आगे चल कर स्मार्ट सिटी में दाग साबित होती है और जनता परेशान होती है।

सील बिल्डिंग में निर्माण की फोटो वायरल

जोन-2 स्थित काकादेव में परिसर संख्या 117-एम-37 में आवासीय नक्शे में अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी। इसपर केडीए ने परिसर सील कर दिया था। मंगलवार को परिसर की फोटो वायरल हुई जिसमें सील इमारत में काम चलता दिखा। इसी तरह से पनकी मंदिर रोड पर बीएमसी हॉस्पिटल का परिसर पांच माह पूर्व सील किया गया था लेकिन उसमें धडल्ले से कार्य करवाया जा रहा है। कल्याणपुर में भी एक सील परिसर में निर्माण कार्य मीडियाकर्मियों ने पकडा था। बताया जा रहा है कि केडीए द्वारा सील की गई अधिकतर इमारतों में कार्य चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मी हर माह मोटी रकम अंदर कर रहे हैं।

-शहर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई उगाही केडीएकर्मी य अन्य कोई करता है तो उसकी शिकायत करें, सतत निगरानी के साथ एक्शन लिया जाएगा।
मदन सिंह गर्ब्याल, उपाध्यक्ष केडीए

खेतों में इस तरह से बेचें जा रहे प्लॉट

का०वि०प्रा०

गया था। इसके बाद 16 अप्रैल 2025 को संचेडी पुलिस को केडीए ने पत्र भेजकर काम रोकने के निर्देश दिए लेकिन फिर भी काम नहीं रूकता है। केडीए ने दोबारा काम रूकवाने का प्रयास किया तो बताया गया कि निर्माणकर्ता ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी बात रखी है। वहीं, इस याचिका की आड में दूसरा खेल सजाया गया है।

इनपुट है कि केडीए के एक अधिकारी लगातार प्रवर्तन दल पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं जब कि आमतौर पर अगर निर्माणकर्ता खुद कोर्ट गया है तो ऐसे में निस्तारण होने तक निर्माण नहीं करना चाहिए

खबर न छापने का बनाया जा रहा है दबाव

केडीए में हर माह अवैध निर्माण रोकने के नाम पर लाखों की उगाही होती है। यह खेल प्रवर्तन दस्ते और दलालों के माध्यम बदस्तूर जारी है। वहीं, जब ऐसे प्रकरणों का खुलासा समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है तो प्राधिकरण में तैनात कुछ अधिकारी और कर्मचारी ब्लैकमेलिंग-उगाही बताकर मीडियाकर्मियों को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। जिससे कि उनका खेल उजागर न हो। स्वराज इंडिया के रिपोर्टर को भी खबर न छापने के लिए विभिन्न प्रकार की धमकियां देकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

लेकिन वह इस आड में अवैध निर्माण कर लेना चाहता है। वहीं, दो दिन पूर्व केडीए ने दोबारा स्थानीय पुलिस एवं डीसीपी को निर्माण को रोकने को लेकर पत्र भेजा है।

केडीए प्रवर्तन कर्मियों से हो चुकी है अभद्रता

केडीए से मिले इनपुट के अनुसार निर्माणकर्ता दीपू चौहान अपने लोगों को आगे करके प्रवर्तन दस्ते से अभद्रता और परेशान कर चुका है। बीते कुछ माह पहले एक चतुर्थ श्रेणी नोटिस देने गया तो उसको धमकाकर लौटा दिया गया। वहीं, दो दिन पहले भी केडीए कर्मी काम रोकने पहुंचे तो रसूक दिखाने का प्रयास किया गया।

बिल्हौर में धूम धाम से मना बकरीद का त्योहार

- ईदगाह और मस्जिदों में हजारों लोगों ने अदा की नमाज
- कस्बों और गाँवों में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर। बिल्हौर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कस्बा स्थित प्राचीन ईदगाह पर सुबह 6 बजे से ही नमाजियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। 7.15 बजे मौलाना अनीसुर रहमान ने नमाज अदा कराई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तहसील का चार्ज संभाले नायब तहसील सीपी राजपूत,एसीपी अमरनाथ यादव, कोतवाल अशोक कुमार सरोज, कस्बा प्रभारी सचिन सिरोही पुलिस बल के साथ तैनात रहे। लोगों ने नमाज पढ़कर एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबार? दी।नमाज के बाद कई घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। मुस्लिम बस्तियों में काफी उत्साह का माहौल रहा। चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन, अरौल मकनपुर आदि कसबो और गाँवों में ईद की नमाज शांतिपूर्व तरीके से अदा की गई।

बिल्हौर- इटावा- लखनऊ राजमार्ग होगा दस मीटर चौड़ा

मार्ग में आने वाले कस्बों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार

लोक निर्माण विभाग जल्द शुरू करेगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य

बिल्हौर- इटावा- लखनऊ राजमार्ग के जल्द बहुरेंगे दिन

रिजवान कुरैशी/ स्वराज इंडिया

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर- इटावा- लखनऊ राजमार्ग के चौड़ीकरण का वर्षों पुराना सपना जल्द साकार होने जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण होने से मार्ग पर आने वाले छोटे- छोटे कस्बों के विकास को पंख लग जाएंगे। यह सड़क सात मीटर से दस मीटर चौड़ी हो जाएगी। शुक्रवार को शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जा चुका है। लोकनिर्माण विभाग जल्द ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरु करेगा।

गौरतलब है कि बिल्हौर- इटावा- लखनऊ राजकीय राजमार्ग की चौड़ाई कुछ वर्षों पहले तक बहुत कम थी। कई कस्बों से होकर गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं था। खराब सड़क होने और कस्बों में जगह जगह अतिक्रमण होने के कारण जगह- जगह जाम लग जाता था।

जब यह सड़क सात मीटर चौड़ी हुई तो लोगों को काफी राहत मिली। और सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी बढ़ गई। अब यह सड़क 10 मीटर चौड़ी हो जाने से बिल्हौर से वाया सिकंदरा इटावा जाने वाले लोगों को इतनी दूरी तय करने में कम समय लगेगा। शासन के इस निर्णय से लोगों में खुशी का माहौल है। बिल्हौर से इटावा जाते समय ककवन, असालतगंज, रसूलाबाद, झींझक, संदलपुर और सिकंदरा सहित कई कस्बे आते हैं। सड़क चौड़ी हो जाने से इन कस्बों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल में शुरू हुई थी सड़क चौड़ीकरण की चर्चा

बिल्हौर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में झींझक से होकर गुजरने के कारण इस मार्ग के चौड़ीकरण की चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन बाद में अब ठंडे बस्ते में चला गया। सड़क किनारे के कई लोग लंबे समय से अपने निर्माण कार्यों को गति देने का इंतजार कर रहे थे। अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। उन्हें जल्द ही बदलाव धरातल पे दिखने लगेगा।

पुलिस ने पकड़ा अवैध वसूली का मास्टरमाइंड

पशु व्यापारी को हाईवे पर रोककर की थी अवैध वसूली, बर्रा पुलिस ने दबोचा

दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बर्रा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण और सहायक पुलिस आयुक्त नौबस्ता के पर्यवेक्षण में, थाना बर्रा पुलिस ने जबरन वसूली के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार किया गया आरोपी नौबस्ता स्थित दुर्गा बिहार का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पशु व्यापारी को हाईवे पर त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास रोककर अवैध रूप से नकदी की वसूली की थी। व्यापारी अपने डीसीएम वाहन से पशुओं को ले जा रहा था, तभी उसे धमकाकर पैसे ऐंठे गए थे।मुखबिर से सूचना मिलने पर बर्रा पुलिस ने आरोपी को भोलेश्वर मंदिर अंडरपास के पास से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया।गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल रहे

थाना प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्रीय चौकी प्रभारी, उपनिरीक्षकगण और महिला होमगार्ड।इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है।

सम्पादकीय

दुरुपयोग आर्थिकी व खेती के लिये घातक

देश के कई राज्यों में रासायनिक खादों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि ने नीति-नियंताओं को चौंकाया है। विशेषकर हरियाणा में यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की खपत में तीव्र वृद्धि ने उर्वरक मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह तथ्य चौंकाने वाला है कि इस रबी के सीजन में हरियाणा में यूरिया खाद का उपयोग अट्ठारह फीसदी तक बढ़ गया है। जबकि कुछ जिलों में डीएपी की खपत में 184 फीसदी का उछाल देखा गया है। दरअसल, रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग और सब्सिडी वाले उर्वरकों की जरूरत से ज्यादा खपत, असामान्य स्थिति का संकेत दे रही है। जिसके चलते अधिकारियों को शंका है कि सब्सिडी वाले नीम कोटेड यूरिया को बड़ी मात्रा में खरीदकर प्लाइवुड, राल व खनन विस्फोटक जैसे उद्योगों के लिये ले जाया जा रहा है। जिनके लिये तकनीकी-ग्रेड वाला यूरिया खासा महंगा पड़ता है। आशंका जतायी जा रही है कि इन व्यवसाय में लगे कुछ लोग इस मूल्य अंतर का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर सब्सिडी वाली खाद की हेराफेरी कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार ये असामाजिक तत्व करीब दस लाख टन यूरिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी कीमत छह हजार करोड़ रुपये बतायी जा रही है। इसकी पड़ताल के लिये केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों के साथ संयुक्त अभियान आरंभ किया है। साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय उर्वरक विभाग आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और रासायनिक खादों के रिसाव पर अंकुश लगाने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। कोशिश है कि किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली खाद के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। आशंका जतायी जा रही है ऐसी कोशिश पर यदि समय पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कालांतर किसानों के लिये खाद की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिसके सामाजिक व राजनीतिक निहितार्थों को समझते हुए केंद्र सरकार के संबंधित विभाग सतर्क प्रतिक्रिया दे रहे हैं।यह तथ्य निर्विवाद है कि खेती में अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। दरअसल, आम किसानों को ठोस जानकारी नहीं मिल पाती कि इसका कितना उपयोग अधिक फसल लेने व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये काफी है। आम किसान पैदावार बढ़ाने के लिये बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं। खासकर नई उच्च नाइट्रोजन वाली गेहूं की किस्मों के लिये। वहीं एनपीके यानी सोडियम, फॉस्फोरस व पोटेशियम उर्वरक की खपत में वृद्धि ने यूरिया पर निर्भरता को और अधिक बढ़ा दिया है। जिससे मिट्टी का क्षरण, कीट जोखिम बढ़ने के साथ ही भूजल प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हो रही है। निर्विवाद रूप से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है बल्कि कृषि भूमि की दीर्घकालीन उपादेयता को भी कम कर रहा है। उर्वरकों की खपत में तेजी से वृद्धि देश की आर्थिकी पर प्रतिकूल असर डाल रही है। उर्वरकों के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता वित्तीय संकट को भी बढ़ावा दे रही है। देश वार्षिक रूप से करीब 75 लाख टन यूरिया का आयात करता है। यूरिया की बढ़ती वैश्विक कीमतों ने उर्वरक सब्सिडी को 1.75 ट्रिलियन रुपये से अधिक कर दिया है। यदि इस स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो बढ़ती उर्वरक मांग अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालेगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार उर्वरक की बिक्री की निगरानी को सशक्त बनाए । सब्सिडी वाली रासायनिक खाद का दुरुपयोग करने वालों के लिये सख्त दंड की व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा किसानों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि खेती में खाद का उपयोग कैसे संतुलित ढंग से किया जाना चाहिए। रासायनिक खाद की बिक्री को अनियंत्रित छोड़ देने से न केवल संकट का असर करदाताओं पर बोझ बढ़ाएगा वरन अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। साथ ही बड़ा संकट इस बात का भी कि खेती में अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से हमारे पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव होगा।

सद्भाव व मानवीय मूल्यों के संवर्धन का महोत्सव

क्षमा शर्मा

भले ही राजनीतिक चश्मे से आलोचना की जाए लेकिन करोड़ों लोगों के आवागमन, संगम में स्नान, सुरक्षा का दायित्व निभाना आसान काम नहीं है। भीड़ का अनुशासन, सहयोग, सद्भाव व सेवाभाव मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है। आध्यात्मिक महत्व से बढ़कर इस जनोत्सव का समरसता व सामंजस्य दृष्टि से महत्व है।पैंतालीस दिन के आयोजन के बाद कुंभ समाप्त हो गया। सरकार ने सोचा था कि इसमें पैंतालीस करोड़ लोगों के आने की सम्भावना है, मगर दावा है कि आये छियासठ करोड़, इक्कीस लाख। यानी कि बीस करोड़ से ज्यादा। चैनल्स पर लगातार जिस तरह से कुंभ के दृश्य दिखाए गए, उससे हैरत होती थी। सिर पर भारी-भारी सामान लादे लोग, पैदल चलते। कोई अपने बूढ़े पिता को गोद में उठाए, कोई स्त्री अपनी सास को पीठ पर लादे, दो लड़के अपनी मां या घर की किसी वृद्ध महिला को सहारा देते।

खुले आसमान के नीचे सोते। एक तरफ से दस से पंद्रह किलो मीटर तक चलना, लेकिन किसी तरह का उत्पात नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई दंगा-फसाद भी नहीं। क्या डेढ़ महीने से अधिक के इतने बड़े आयोजन के बावजूद, इतनी अनुशासित भीड़ किसी ने देखी है। यूरोप की आबादी से भी यह भीड़ बस कुछ कम है। अमेरिका की कुल आबादी चौंतीस करोड़ है और पूरे यूरोप की चौहत्तर करोड़। यदि किसी दूसरे देश में इतनी भीड़ इकट्ठी हो, लगातार आ रही हो, तो वहां क्या होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।कुंभ को लेकर विपक्ष की जो भूमिका रही, उस पर आश्चर्य होता है। आप भाजपा सरकार का विरोध कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, मगर जो लोग इतनी लम्बी-लम्बी यात्राओं के बाद प्रयागराज आए, उनकी आलोचना करने और मजाक उड़ाने का क्या अर्थ है। किसी की भावनाओं को अपने-अपने राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या उन लोगों के वोट विपक्ष को नहीं चाहिए। देश के दूर-दराज के इलाकों से ही नहीं, विदेशों से भी बहुत से लोग आए। एक से एक बड़े लोग आए। बड़े-बड़े नेता आए। उद्योगपति आए। अम्बानी सपरिवार आए। अडानी ने तो वहां बड़े स्तर पर खाने-पीने का प्रबंध किया। कैटरीना कैफ, रवीना टंडन, विक्की कौशल, अनुपम खेर, ममता कुलकर्णी, मिलिंद सोमन, राजकुमार राव, अक्षय कुमार जैसे अनेक अभिनेता, अभिनेत्रियां भी आए। क्या ये सब मजाक उड़ाने लायक हैं। और क्यों। आप कौन होते हैं किसी का मजाक उड़ाने वाले। किसने ये अधिकार दिया। इतनी संवेदनहीनता की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। सच तो ये है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो अपना मजाक उड़वाने की तैयारी कर रहे होते हैं।कई परिचित कुंभ में गए थे। बहुराष्ट्रीय निगम में काम करने वाली एक लड़की भी गई थी। बाकी जहां रहती हूं, वहां से भी बहुत से लोग गए थे। सभी ने एक सुर में कहा कि वहां इंतजाम बहुत अच्छे थे। कोई बीमार पड़ा तो उसे तत्काल इलाज की सुविधा मिली। खास तौर से पुलिस की भूमिका बेहद सराहनीय थी। उसी लड़की ने कहा कि वह जिनके साथ गई थी, उनसे बिछुड़ गई। घबराहट में रोने लगी। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आया। सारी बात जानकर उसने कहा- रोओ मत। अभी मैं तुम्हें मिलवाता हूं। फिर उसने लड़की से उन लोगों के नम्बर लिए जिन्हें लड़की मिला रही थी और मिल नहीं रहे थे। उसने काफी प्रयास के बाद उन लोगों से सम्पर्क साधा और लड़की को मिलवाया।इसी तरह गुड़गांव की एक महिला को पुलिस ने रोते देखा । पूछने पर पता चला कि वह गुड़गांव से आई है, साथ वालों से बिछड़ गई है। उसे पता नहीं कि अकेली कैसे लौटना है। पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया। कहा कि अगर उसके साथ के लोग नहीं मिले, तो वे उसे गुड़गांव तक छोड़कर आएंगे। कुंभ के समापन के दिन पुलिस ने बताया कि इस दौरान तीस हजार बिछड़े लोगों को मिलवाया गया। तीस हजार कोई मामूली संख्या नहीं है। पुलिस के अच्छे कामों की शायद ही कभी सराहना की जाती है। बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग अक्सर बाल की खाल निकालने को तत्पर रहते हैं। क्योंकि किसी की तारीफ करने के मुकाबले आलोचना करना बड़ा आसान है। इतनी बड़ी भीड़ का प्रबंधन कैसे किया गया होगा। सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने अपने को झोंक दिया होगा। कुंभ के बाद न जाने कितने दिन इन लोगों को अपनी थकान उतारने में लगेंगे। पर इनकी चिंता भला किसी को क्यों हो ।

लेकिन हम इन सब बातों को याद नहीं रखेंगे। सिवाय तरह-तरह से आलोचना करने के। यह बात अलग है कि जब हमारे घर में शादी-ब्याह होता है, तो हम मात्र सौ-पचास लोगों का इंतजाम करने में सारी ताकत झोंक देते हैं। सिर के बल खड़े हो जाते हैं, फिर भी आने वाले खुश नहीं होते। यही हाल किसी सभा-सेमिनार का होता है। तो हम तो सौ-पचास का इंतजाम करने में घबरा जाते हैं, मगर आलोचक बनते वक्त परम निंदक बन जाते हैं।

प्रयागराज में कुंभ के दौरान जो हादसा हुआ, लोगों की जान गई, या कि नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ में लोगों की जान गई वह बहुत दर्दनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी परिवार के लिए अपने परिजन की जो कीमत होती है, वह वही जानता है। लेकिन इसमें कुंभ का क्या दोष। वहां आने वाले श्रद्धालुओं को क्यों हम अपने चश्मे से देख रहे हैं। या वे इस देश के नागरिक नहीं। फिर उन्हें यहां आने के लिए शायद ही किसी तरह की सरकारी सहायता दी गई है। जिस से जो साधन बना, वह उसके जरिए यहां पहुंचा।

न्यायपालिका में पारदर्शिता की ओर पहलकदमी

संशोधन विधेयक 2025

डा0 सुधीर कुमार

न्यायपालिका में पारदर्शिता-जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 न्यायपालिका में सुधार की दिशा में नया कदम है। इससे कानूनी पेशे का दायरा व सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, नागरिकों को विविध कानूनी मदद प्राप्त करना आसान होगा। हालांकि प्रस्तावित विधेयक पर विचार-विमर्श कर बीसीआई और वकीलों की चिंताओं को संबोधित करना जरूरी है।

भारत की न्यायपालिका, जो न्याय और समानता की आधारशिला है, हमेशा से ही सुधारों की मांग करती रही है।

लंबित मामलों का बोझ, ऊंच-नीच के आरोप और प्रक्रियात्मक जटिलताओं ने न्यायपालिका की दक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधान है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है, जो भारत में कानूनी पेशे को नियंत्रित करता है।

पहले, 1961 के अधिनियम के अनुसार, कोर्ट में वकालत करना ही कानूनी व्यवसाय माना जाता था। लेकिन, नए विधेयक में कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को और बढ़ा दिया गया है। अब, कानूनी व्यवसाय में कोर्ट में वकालत करने वालों के अलावा वे सभी लोग शामिल होंगे जो कानून से जुड़े अलग-अलग कामों में लगे हैं, जैसे कि कंपनियों के लिए कानूनी काम, कॉन्ट्रैक्ट बनाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े काम। इस बदलाव से कानूनी पेशे का दायरा बढ़ गया, इसमें कई तरह के कानूनी काम शामिल हो गए हैं। इससे कानूनी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को विविध कानूनी मदद प्राप्त करने में आसानी होगी।

वर्तमान में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 4 में संशोधन करके केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि

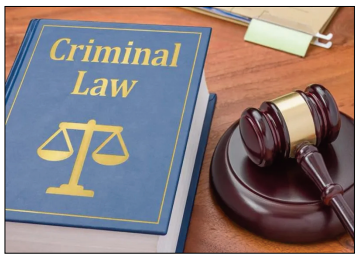

वह बीसीआई में मौजूदा निर्वाचित सदस्यों के अलावा 3 सदस्यों को नामित कर सके। यह संशोधन सरकार को कानून के प्रावधान लागू करने में बीसीआई को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करेगा।वर्तमान में, अपने मुवक्किल को धोखा देना पेशेवर कदाचार माना जाता है, जिसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया से की जाती थी। हालांकि, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 45बी के तहत, पेशेवर कदाचार के कारण यदि किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वह बीसीआई में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी हड़ताल के कारण किसी का नुकसान होता है, तो यह वकील का पेशेवर कदाचार माना जाएगा। यह संशोधन मुवक्किलों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित करता है। यह प्रावधान वकीलों को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने मुवक्किलों के हितों की रक्षा करें।

अभी तक, एक वकील एक साथ कई बार एसोसिएशनों का सदस्य हो सकता था और उन सभी में चुनाव के दौरान वोट भी कर सकता था। लेकिन, नए विधेयक में धारा 33ए जोड़ी गई जिसके अनुसार, अदालतों, ट्रिब्यूनलों और प्राधिकरणों में वकालत करने वाले वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां वे वकालत करते हैं। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं, तो 30 दिनों के भीतर बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। अब वकील एक से अधिक बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हो सकते और केवल एक बार एसो. में वोट कर सकते हैं।मौजूदा व्यवस्था में, हड़ताल करना गैरकानूनी नहीं था, लेकिन पेशेवर कदाचार माना जाता था। हालांकि, नए विधेयक में धारा 35ए जोड़ी गई है, जो किसी वकील या वकील संगठन को अदालत के बहिष्कार का आह्वान करने, हड़ताल करने या काम रोकने से रोकती है। इस धारा का उल्लंघन वकालत पेशे का कदाचार माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लेकर वकीलों में कई चिंताएं हैं। उनका मानना है कि इसके कुछ प्रावधान उनके अधिकारों का हनन और न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। तर्क है कि धारा 35ए उन्हें अपनी बात रखने और समस्याएं उठाने के लिए हड़ताल-बहिष्कार जैसे महत्वपूर्ण हथियारों से वंचित करती है। वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि यह धारा उनकी आवाज दबाने जैसी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकती है।विधेयक की धारा 35 में वकीलों पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वकीलों का मानना है, यह जुर्माना उन पर अनावश्यक दबाव डालेगा और उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, नए कानून के अनुसार, अगर किसी की शिकायत झूठी या बेकार साबित होती है, तो उस पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। लेकिन, यदि किसी वकील के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है।

बरात रुकवाने थाने पहुंची प्रेमिका पुलिस ने घंटों बैठाया, फिर लौटी बारात

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। गुरुवार को युवक की बरात महोबा जाने की सूचना पर घर पहुंची तो युवती को प्रेमी ने परिजनों ने गाली गलौच कर भगा दिया। इसके बाद युवती ने कोरियां चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। कानपुर स्थित सेन पश्चिम पारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमी युवक की बरात रुकवाने गुरुवार को कोरियां चौकी पहुंची युवती ने पुलिस पर चौकी में बैठाने का आरोप लगाया है। उधर, लड़की पक्ष को यह पता चला तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। बिना दुल्हन के बरात लौट आई।

चार साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

नौबस्ता थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने बताया कि सेन पश्चिम पारा थाने की कोरियां चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने उसके बालिग होने पर शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बालिग होने पर शादी दबाव बनाया तो मारपीट कर दी।

प्रेमी के घर वालों ने गाली गलौच कर भगाया

गुरुवार को युवक की बरात महोबा जाने की सूचना पर घर पहुंची तो युवती को प्रेमी ने परिजनों ने गाली गलौच कर भगा दिया। इसके बाद युवती ने कोरियां चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस ने उसे कार्रवाई का भरोसा दिलाकर घंटों चौकी में बैठाए रखा। युवक बरात लेकर निकल गया।

112 पर नहीं मिली मदद

आरोप है कि कई बार डायल 112 कंट्रोलरूम में भी सूचना दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सेनपश्चिम पारा थाना प्रभारी कुशल पाल सिंह ने बताया कि बरात जाने के बाद युवती चौकी पहुंची थी। पुलिस द्वारा चौकी में बिठाने की बात निराधार है। बरात वापस आने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

दुल्हन के घरवालों ने शादी से किया इनकार

वहीं, युवक के परिजनों ने बताया कि इस मामले की जानकारी महोबा में लड़की के परिजनों को गई तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जिस पर शुक्रवार को बरात बिना दुल्हन के लौट आई।

जुलाई में गली-गली नजर आएगा पराग का दूध, दही व पनीर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेगा संचालन

- निरालानगर में 1962 में बना प्लांट
- 10 साल लीज पर प्लांट होगा संचालित
- एक हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर शहर की गली और मोहल्लों में लंबे समय के बाद पराग का दूध, दही, छाछ, पनीर समेत अन्य उत्पाद नजर आएंगे। जुलाई से नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) दस वर्ष की लीज पर पराग डेयरी प्लांट का संचालन करने जा रहा है। शासन की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, जबकि इस हफ्ते करार हो सकता है। जून के अंत तक चार लीटर क्षमता के प्लांट का ट्रायल होगा।

निरालानगर की लगभग 56 एकड़ जमीन पर 1962 में पराग डेयरी का 50 हजार लीटर क्षमता का प्लांट बना था। उस समय कानपुर और कानपुर देहात से दूध आता था। करीब 20 हजार लीटर पराग के दूध की बिक्री होती थी, लेकिन धीरे-धीरे समय बीता और मशीनें खराब होने लगीं। वर्ष 2013 में प्लांट बंद कर दिया गया, जिससे पराग की बिक्री भी ठप हो गई। इस दौरान कई निजी कंपनियों ने पांव पसार दिए। प्लांट के संचालन को लेकर कई प्रयास हुए। परिसर में 12 अप्रैल 2016 को आधुनिक प्लांट का शिलान्यास हुआ। वर्ष 2020 में करीब 166 करोड़ की लागत से दो लाख लीटर दूध और दो लाख लीटर पाउडर बनाने की क्षमता का प्लांट तैयार हुआ। यह प्लांट कर्मचारियों से लेकर विभिन्न विभागों की करीब 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी होने से चल नहीं सका। आधुनिक प्लांट भी संचालित नहीं हुआ।

प्रमुख सचिव दुग्ध विकास के. रविंद्र नायक ने मई के अंत में एनडीडीबी से सहमति कर शासनदेश जारी कर दिया है। पराग प्लांट को 10 साल के लिए लीज पर देने की स्वीकृति हुई है। अक्टूबर 2023 में निजी क्षेत्र के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेशनल डेयरी द्वारा प्लांट को संचालित करने का प्रस्ताव आया तो, कानपुर दुग्ध संघ ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। शासन ने भी नेशनल डेयरी पर अंतिम मुहर लगा दी। उत्पाद पराग के नाम से रहेंगे।

डेयरी के संचालन से शहरवासियों को लाभ मिलेगा। यहां पर दूध के साथ दही, मक्खन, दूध पाउडर, पनीर, मट्ठा आदि का उत्पादन होगा। संचालन से करीब एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पुराने कर्मचारियों को भी काम मिलने की उम्मीद है। बकायेदारों और कर्मचारियों की देनदारी मंथन चल रहा है।

नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड से सहमति हो चुकी है। इसी हफ्ते करार भी हो जाएगा। जून के अंत तक प्लांट का ट्रायल होगा, जबकि जुलाई से लोगों को दूध, दही और अन्य उत्पाद मिलने लगेंगे। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, इसे आसपास के जिलों में भेजा जाएगा।

ओवरटेक करने में उड़े कार के परखच्चे, कटर से काटकर महिला का निकाला, बाल-बाल बचे पति और बेटा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर के घाटमपुर कस्बे में शुक्रवार सुबह हमीरपुर से कानपुर जाने के दौरान शुक्ला पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित हुई कार आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। तभी पीछे से आ रहा ट्रक भी कार में जा घुसा। हादसे में कार के आगे व पीछे से परखच्चे उड़ गए।कार में आगे बैठी महिला, जहां काफी देर तक सीटों के बीच में फंसी रही। वहीं साथ में जा रहे पति व कार चला रहा बेटा बाल-बाल बच गए। दोनों लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से किसी तरह फंसी महिला को बाहर निकाला।उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सीएचसी लाया गया। जानकारी के अनुसार, जनपद हमीरपुर के रहने वाले सुरेशचंद्र (55) अपनी पत्नी नीलम (50) व बेटे सूरज (30) के साथ कानपुर जा रहे थे। बेटा कार चला रहा था और जैसे ही वह हमीरपुर रोड पर स्थित शुक्ला पेट्रोल पंप के पास पहुंचे।तभी आगे जा रहे ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में कार आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक भी कार में जा घुसा। हादसा देख पहुंचे लोगों ने किसी तरह पिता-पुत्र को कार से शीशे तोड़कर बाहर निकाला।घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीटों के बीच फंसी नीलम को कटर की मदद से किसी तरह काफी देर बाद बाहर निकाला। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सीएचसी से हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज किया जा रहा है।

आठ को बिल्हौर आ सकते हैं सीएम योगी

- 12 जून तक प्रदेश में हो रहे हैं अलग-अलग कार्यक्रम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर के बिल्हौर में आठ जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को सम्मानित करने के लिए आ सकते हैं। इस संबंध में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए मक्का व आलू समेत दूसरी फसलें उगाने वाले किसानों को चिह्नित किया जा रहा है।बिल्हौर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अरौल के सरैया में खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक कृषि तकनीकी व जलवायु परिवर्तन कृषि पद्धतियों की जानकारी तीन जून को किसानों को दी थी। 12 जून तक प्रदेश में अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री यहां आ सकते हैं।

बड़े भाई ने सूजा घोंपकर की छोटे भाई की हत्या

» बिजली का बिल न जमा करने पर हुआ था विवाद

» सूजे से पेट पर तबाड़तोड़ वार

» बिजली के बिल को लेकर हुआ था विवाद

» हत्यारोपी मौके से फरार, तलाश में जुटी टीमें

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बादशाहीनाका थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई की सूजा घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी जितेंद्र मौके से भाग निकला। पुलिस तलाश में दबिश दे रही है।कानपुर में ईद पर्व पर बादशाहीनाका थाना क्षेत्र में बिजली का बिल जमा न करने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को सूजा घोंपकर मार डाला। इससे परिवार में कोहराम मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की है।

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के हुसैन अफसर तिराहा गुलियाना निवासी विजेंद्र यादव (34) और जितेंद्र यादव दो भाई हैं। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इस महीने बिल ज्यादा आ गया था। बिल जमा न होने के चलते चार दिन पहले बिजली कट गई थी।

इससे पूरा परिवार परेशान हो रहा था। इसी बात को लेकर शनिवार सुबह दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। इस दौरान बड़े भाई जितेंद्र ने छोटे भाई विजेंद्र को थप्पड़ मार दिया। इस पर विजेंद्र ने भी विरोध करते हुए मारपीट कर दी।

इस बात को लेकर आक्रोशित भाई ने घर में रखा बर्फ काटने वाले सूजे से पेट में ताबड़तोड़ वार करके विजेंद्र की हत्या कर दी। खून देखकर परिवार में कोहराम मच गया और उसे आनन-फानन में उर्सला अस्पताल ले गए। यहां

पर जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एडीसीपी अंजली विश्वकर्मा फोर्स के साथ पहुंची और जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने जिस सूजे से हत्या की गई खून से सने हुए हालत में उसे भी बरामद कर लिया। हत्या करने के बाद आरोपी जितेंद्र मौके से भाग निकला। पुलिस तलाश में दबिश दे रही है।

सिंगल पिलर पर बनेगी नरोना से किदवई नगर तक एलिवेटेड रोड

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नरोना चौराहा से घंटाघर, टाटमिल होते हुए किदवई नगर तक जाने वाली सड़क पर एलिवेटेड रोड का निर्माण सिंगल पिलर पर होगा। इसके निर्माण से घंटाघर, नरोना चौराहा, टाटमिल चौराहा और किदवई नगर चौराहा पर लगने वाला जाम समाप्त हो जाएगा। साथ ही लोगों को आवागमन में भी आसानी होगी। नरोना चौराहा से किदवई नगर की दूरी छह किलोमीटर है। यह एलिवेटेड रोड पूरी छह किलोमीटर नहीं बनेगी, जहां- जहां जरूरत है वहीं इसका निर्माण होगा। जल्द इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। चूंकि केडीए इसके निर्माण के लिए धनराशि खर्च करने जा रहा है ऐसे में शासन से बजट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोजेक्ट भी आसानी से निर्धारित अवधि में पूरा हो जाएगा।शहर में जाम बड़ी समस्या है। दक्षिण क्षेत्र जैसे किदवई नगर, नौबस्ता,गोविंद नगर, यशोदानगर, कर्रही, बर्रा, विश्व बैंक बर्रा, साकेत नगर, बारादेवी आदि इलाकों में रहने वाले लोगों को सिविल लाइंस, घंटाघर, मालरोड, आर्यनगर , स्वरूप नगर आदि क्षेत्रों में आने के लिए कई जगहों पर जाम से जूझना पड़ता है। कई बार तो लोगों की ट्रेन तक छूट जाती है क्योंकि किदवईनगर की तरफ से आते समय सबसे ज्यादा जाम टाटमिल चौराहे पर लगता है। टाटमिल चौराहा पार करने के बाद घंटाघर पुल और घंटाघर चौराहे पर जाम से जूझना पड़ता है।

शिक्षक की पत्नी से ठगी, एटीएम बदलकर 47 हजार उड़ाए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नौबस्ता में शिक्षक की पत्नी ठगी का शिकार हो गई। शातिर ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से छह बार में 47,700 रुपये पार कर लिए। पैसे निकलने का मैसेज आने पर पीड़िता को घटना की जानकारी हुई। इस पर तत्काल थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन सुनवाई न करने पर एडीसीपी दक्षिण से कार्रवाई की मांग की है। आवास विकास हंसपुरम निवासी संजय कुमार शर्मा शिक्षक हैं और उनकी तैनाती घाटमपुर में है। उनकी पत्नी आरती का बर्रा स्थित इंडियन बैंक में खाता है। आरती के अनुसार चार जून की सुबह उन्होंने अपनी भतीजी मौली को खाते से रुपये निकालने के लिए भेजा था। मौली क्षेत्र के एसबीआई एटीएम में रुपये निकालने पहुंची, लेकिन रुपये नहीं निकले।इसी दौरान एक युवक एटीएम पर आया और मौली को झांसे में लेकर कार्ड बदल लिया। पैसे न निकलने पर मौली के एटीएम से बाहर आई और वहां से चली गई। इसके बाद आरोपी ने तीन बार में 25 हजार रुपये नकद निकाले। लिमिट खत्म होने पर लाडो इंटरप्राइजेज से तीन बार में 22,700 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। आरती के अनुसार पैसे निकलने का मैसेज आने के बाद उन्होंने 1930 पर काल की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद बैंक और पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने कोई सुनवाई की तो एडीसीपी दक्षिण से शिकायत की। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिक्षक बताकर हड़प लिए छह हजार

कानपुर। बाबूपुरवा के टीपीनगर निवासी छोटा बाबू से एक अंजान व्यक्ति ने खुद को उनके बेटे का शिक्षक बताकर ठगी की। कहा कि आपरेशन के लिए 12 हजार रुपये की जरूरत है। इस पर उन्होंने बताए गए मोबाइल पर पांच बार में छह हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्होंने शिक्षक को फोन किया तो उन्हें ठगी का पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।किदवईनगर में बुधवार रात छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने नकदी व जेवर समेत डेढ़ लाख का माल पार कर ले गए। गुरुवार सुबह सोकर उठे परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है।जूही सफेद कालोनी में धर्मेंद्र गौतम के मकान में किराए पर रहने वाली लक्ष्मी पाल लोगों के घरों में खाना बनाती हैं। परिवार में पति मुनीश, बेटा विवेक और पिता जोर सिंह हैं। लक्ष्मी ने बताया कि बुधवार रात परिवार समेत कमरे में सो रही थीं। गर्मी के चलते मुख्य दरवाजा खुला था, जिसका फायदा उठाकर छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने अलमारी में रखे 42 हजार रुपये नकद और दो जोड़ी,पायल, मंगलसूत्र, नाक की कील, झुमकी समेत एक लाख रुपये से अधिक के जेवर समेट ले गए। किदवईनगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक कैद मिले हैं। उनकी पहचान कराकर तलाश की जा रही है।

यातायात नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई, वाहन सीज व चालान

» भोगनीपुर में चला विशेष अभियान, ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाहनों पर कसा शिकंजा

» डीएम और एसपी के निर्देशन में संयुक्त टीम की सख्ती, सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह और पुलिस अधीक्षक अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद में यातायात नियमों के प्रति सख्ती बरती जा रही है। सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शनिवार को भोगनीपुर क्षेत्र में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान का नेतृत्व उपजिलाधिकारी भोगनीपुर, क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर और एआरटीओ कानपुर देहात ने संयुक्त रूप से किया। अभियान के दौरान सड़क पर चलने वाले ओवरलोड वाहन, बिना नंबर प्लेट, और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की गहन जांच की गई।

इस दौरान कई वाहनों को नियमों के विरुद्ध पाया गया, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई। कुल 14 वाहनों के चालान किए गए और एक वाहन को सीज कर लिया गया। सभी कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई।

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान न केवल नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए था, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी एक प्रयास है। आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और भी सघन किए जाएंगे, ताकि जनपद में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

टीम द्वारा यह भी अपील की गई कि वाहन चालक नंबर प्लेट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों को अद्यतन रखें तथा तय सीमा में लोडिंग करें, जिससे स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा बनी रहे।

इस संयुक्त अभियान को लेकर आम नागरिकों में चर्चा बनी रही और जनमानस ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया।

युवक ने जामुन के पेड़ पर लगाई फांसी

» डेरापुर क्षेत्र के भढ़ावल गांव में फंदे से लटका मिला शव, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भढ़ावल में गुरुवार सुबह एक युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांव निवासी जसवंत संखबार का 20 वर्षीय पुत्र अंकित अपने ही घर के बाहर लगे जामुन के पेड़ पर साड़ी से बने फंदे के सहारे मृत पाया गया।घटना की जानकारी मिलते ही डेरापुर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

थाना प्रभारी महेश कुमार के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

घटना से गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

अरविंद राठौर बने रसूलाबाद लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष

» निकटतम प्रतिद्वंदी को 17 वोटों से पराजित किया

» साथी अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। द लॉयर्स एसोसिएशन रसूलाबाद कानपुर देहात का वार्षिक चुनाव शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह राठौर विजयी घोषित किए गए।

उन्होंने हुकुम सिंह राजपूत को 17 वोटों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सर्वेश कुमार पाल एडवोकेट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भुवनेंद्र यादव को 28 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की तथा महामंत्री पद के प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने अपने प्रतिद्वंदी मनीष दीक्षित को हराकर अपनी जीत दर्ज की। वहीं कोषाध्यक्ष अर्पित यादव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिपाठी की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। इसी बीच परिणाम घोषित होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश चतुर्वेदी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी, अजय पाल राजपूत , श्रीकांत दीक्षित , गगन तिवारी, कमलेश कुमार मिश्रा , रुद्रसेन अवस्थी , सुशील कुमार शुक्ला, हरनाम सिंह कुशवाहा, कमलेश कुमार संखवार, रब्बानी खान, विष्णु श्रीवास्तव, श्रवण कुमार बाजपेई, पीसी वर्मा, श्री सुमित कुमार गौतम, यशवंत सिंह, जय नारायण राठौर, सुरेंद्र सिंह राठौर ,वीरेंद्र सिंह सेंगर, विनोद दिवाकर, हनुमान सिंह

यादव, राम सिंह यादव, सत्येंद्र प्रकाश यादव , योगेंद्र सिंह यादव, दयाराम पाल, जय गोपाल राठौर , महेश चंद्र वर्मा, कुलदीप अवस्थी यादव, अनिल कुमार वर्मा, उदयवीर चौहान वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष श्री संतोष सिंह गौर पूर्व अध्यक्ष श्री बलराम सिंह चौहान, तीरन सिंह नैयर, उपेंद्र यादव, बीपी सिंह यादव, वीर प्रताप पाल, राम सिंह पाल, पूर्व महामंत्री भीष्म प्रताप पाल , दिलीप पाल, साधु सिंह यादव, शिवपाल गौतम, राजेश कुशवाहा , सौरभ राजपूत आदि सभी अधिवक्ता साथियों ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लादकर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करा कर हर्ष व्यक्त किया।

भोगनीपुर की बदहाली पर सख्त प्रशासन, संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण

ग्राम प्रधान और अफसरों की लापरवाही से नाराज़ ग्रामीण, मामला पहुंचा सीएम कार्यालय तक

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर गांव की लगातार मिल रही जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी भोगनीपुर जितेंद्र कटियार ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल की संयुक्त टीम गांव भेजी। टीम को गांव की जमीनी स्थिति देख दंग रहना पड़ा हर गली में बहता गंदा पानी, जाम नालियां, टूटी सड़कें और दुर्गंध देते तालाब प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहे थे। ग्रामीणों कैलाश शंखवार, वीरू, पप्पू ठाकुर, सरताज अली आदि ने टीम को गांव के हालात दिखाए। तालाब का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा था।

ग्राम प्रधान की अनदेखी पर नाराज ग्रामीण

करीब छह माह से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की निष्क्रियता से परेशान ग्रामीण लगातार डीएम, एसडीएम और मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें भेज रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास कार्यों की अनदेखी कर ग्राम प्रधान सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम ने टीम से रिपोर्ट तैयार कराई जो उन्हें सौंप दी गई है। अब ग्राम प्रधान व बीडीओ पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज का फटा मोबाइल

इस घटना से वार्ड में मौजूद मरीज और तीमारदार घबरा गए

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शनिवार सुबह एक अजीब घटना सामने आई। एक मरीज की जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक धमाके के साथ फट गया।

उज्जवल नगर के अवनीश पाल लखनऊ जाते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। स्थानीय लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान अवनीश की जेब में रखे मोबाइल से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद फोन में विस्फोट हुआ और आग लग गई।

इस घटना से वार्ड में मौजूद मरीज और तीमारदार घबरा गए। अस्पताल कर्मचारियों ने तत्काल फायर सिलेंडर से आग बुझाई। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मोटोरोला कंपनी का यह मोबाइल एक्सीडेंट में पहले से क्षतिग्रस्त था। माना जा रहा है कि डैमेज फोन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी।

1 किलो से अधिक गांजे के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

स्वराज इंडिया संवाददाता

निंदूरा (बाराबंकी)। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गी के निर्देश पर बाराबंकी के बड़ुपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर अपराधी को एक किलो नौ सौ ग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आपको बताते चलें कि संदिग्ध व्यक्तियों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बड़ुपुर पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान दौरान बाबा कुटी शारदा सहायक नहर पुल के पूर्वी पटरी पर दो संदिग्ध व्यक्ति सावंत कुमार पुत्र रमाशंकर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लोहजागर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर व चौधरी ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम टीवी अस्पताल के सामने गली में थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच को जमा तलाशी के दौरान एक किलो नौ सौ ग्राम अवैध गांजा, मोटरसाइकिल एक्टिवा, दो सौ पचास रुपए नगद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल को रवाना कर दिया। गिरफ्तारी पुलिस टीम में थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह,उप निरीक्षक निष्कर्ष चौरसिया,हेड कांस्टेबल गणेश बाबू,कांटेबल अम्बरीष वर्मा,आशीष यादव शामिल रहे।

हर्षोल्लास व अकीकद से मनाया गया ईद-उल-अज़हा

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। हर्षोल्लास व अकीकद से जिले में मनाया गया ईद-उल-अज़हा का पर्व। प्रशासन द्वारा ईदगाह परिसर के अंदर ही नमाज अदा करने के निर्देश के अनुपालन में क्षेत्र के अनेक मस्जिदों में 5:45 से शुरू होकर 7:30 बजे तक नमाजे अदा की गई। बाराबंकी जनपद के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नवाज अदा की गई, इस दौरान ईदगाह के जिम्मेदारों द्वारा नमाजियों से सड़क पर नमाज ना पढ़ने की लगातार अपील जारी किया।

बताते चलें कि नई ईदगाह में इमाम ईदगाह हाफ़िज़ अजीजुद्दीन द्वारा बकरा ईद की नमाज अदा कराई गई। इसके पश्चात सैकड़ो की संख्या में उपस्थित नमाजियों ने देश में अमन चैन और भाईचारे की तरक्की के लिए दुआ मांगी। ईदगाह के बाहर जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों द्वारा गले मिलकर नमाजियों का इस्तकबाल किया। इसी क्रम में बड़ापुरा स्थित पुरानी ईदगाह में कारी मोहम्मद हलीम द्वारा ईद-उल-अज़हा की नमाज अदा कराई व देश दुनिया में अमन के लिए दुआएं मांगी। तो वहीं शिया जामा मस्जिद में मौलाना सरफ़राज़ हुसैन द्वारा ईद-उल-अज़हा की नमाज अदा कराई और अली अकबर कटरा सहित क्षेत्र की अन्य ईदगाहों में भी इमामो द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से नमाजे अदा कराई। ईद-उल-अज़हा पर्व पर

नमाजियों ने देश में अमन चैन और भाईचारे की तरक्की के लिए दुआ मांगी

प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। इस दौरान पर्व में होने वाली कुर्बानी के अवशेष के लिए गड्ढो की खुदाई, साफ-सफाई व्यवस्था, चूना छिड़काव और मस्जिदों के आसपास साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कराया गया। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में गस्त कर लोगों में सुरक्षा का आभास कराता रहा। चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अलीम द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने के साथ कुर्बानी के अवशेष नगर प्रशासन द्वारा निर्धारित खड्डो में डालने की अपील की गयी।

(अयोध्या की अफीम कोठी पर ग्राउंड रिपोर्ट)

भ्रष्टाचार और मनमानी की नींव पर खड़ा हो रहा साकेत सदन

- साकेत सदन की दीवारों में कैद अतीत की शान और अफसरों का कागजी खेल
- साकेत सदन का 77 प्रतिशत कार्य हुआ पूर्ण-डीएम
- 16.33 करोड़ की लागत से पर्यटन विभाग करा रहा साकेत सदन का सौंदर्यीकरण

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या एक ऐसा शहर जो इतिहास, आध्यात्म और राजनीति के संगम से भरा पड़ा है, वहां एक ऐतिहासिक इमारत चुपचाप समय की मार सह रही है साकेत सदन। किसी समय मुग़लिया सल्तनत का दिलकुशा महल और फिर अंग्रेजी हुकूमत की अफीम कोठी रही यह संरचना आज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन कागजों पर ज्यादा और धरातल पर बेहद कम।

इस इमारत का निर्माण 1756 और 1775 के बीच अयोध्या के प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर हुआ था। कालांतर में यह अंग्रेजों की अफीम कोठी बनी और अब इसे ओपन एयर थिएटर और रेस्टोरेंट के रूप में संवारने का प्रयास हो रहा है। पर्यटन विभाग के इस प्रोजेक्ट की लागत 16 करोड़ 82 लाख रुपए तय की गई है।

यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई-11 को इस निर्माण कार्य की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसकी निगरानी में अयोध्या में आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तय योजना के अनुसार यह काम अप्रैल 2023 से शुरू होकर मार्च 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन, अयोध्या के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह यहां भी सुस्ती साफ नजर आती है।

राजस्थान के कारीगरों से लाल पत्थरों की नक्काशी और पारंपरिक तकनीकों से ईंटों को पीसकर सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, परंतु निर्माण मानकों की धज्जियाँ भी खुलेआम उड़ रही हैं। दीवारों पर भगवान भरोसे काम चल रहा है और कागजों पर योजनाओं की सजावट खूब हो रही है।

जबाव से भागते जिम्मेदार

जब ग्राउंड पर मौजूद विभागीय इंजीनियरों से सवाल किए गए, तो कोई भी सामने नहीं आया। जेई और संबंधित अधिकारी ऑफिस से नदारद मिले, जहां सिर्फ कुछ छोटे कर्मचारी और एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता दिखाई दिया। जवाब देने वाले अफसर लखनऊ में बैठे हैं, जबकि निर्माण अयोध्या में हो रहा है।

प्रशासन में भ्रम की स्थिति

यह स्पष्ट नहीं कि साकेत सदन की निगरानी किसके जिम्मे है ङ्क नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार या क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी राजेंद्र कुमार? सवाल करने पर कोई भी अधिकारी स्पष्ट उत्तर नहीं देना चाहता। सवाल उठता है कि जिस तरह से करोड़ों खर्च हो रहे हैं और काम की रफ्तार कछुए जैसी है, ऐसे में क्या यह जनता के पैसों का सही उपयोग है? आवश्यक है कि इन तमाम निर्माण कार्यों की पारदर्शी जांच हो और दोषी विभागों व अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए।

साकेत सदन का 77 प्रतिशत कार्य हुआ पूर्ण-डीएम

जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फुण्डे ने बताया कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ तमाम घाटों पार्कों पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। साकेत सदन का अब तक 77 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

अयोध्या की ऐतिहासिक इमारतें सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें सजाने-संवारने की कोशिश होनी चाहिए ईमानदारी से, न कि सिर्फ तस्वीरों और रिपोर्टों तक सीमित। साकेत सदन को सिर्फ इमारत नहीं, अतीत की विरासत समझना होगा।

महिला अस्पताल के एसएनसीयू में जुड़वा समेत तीन नवजातों की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बदायूं। बदायूं के महिला अस्पताल में संचालित एसएनसीयू में वेंटीलेटर नहीं है, जिससे नवजातों के इलाज में बाधा आ रही है। शनिवार को तीन नवजातों की मौत हो गई। इनमें दो जुड़वा थे। बदायूं के महिला अस्पताल में संचालित एसएनसीयू (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई) में वेंटीलेटर न होने से शनिवार सुबह तीन नवजातों की मौत हो गई। यहां इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाने से आठ से दस बच्चों को हर रोज अलीगढ़ व सैफई के लिए रेफर किया जा रहा है।

दातागंज के मोहल्ला परा निवासी धर्मपाल ने पत्नी प्रेमलता को पांच जून के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। देर शाम उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन 780 ग्राम था। बच्चे को एसएनसीयू में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन छह जून को डॉक्टर ने वेंटीलेटर की आवश्यकता बताकर बच्चे को रेफर करने की बात परिजनों से कही, लेकिन परिजन रेफर कराने को तैयार नहीं हुए। शनिवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहां मौजूद स्टाफ के भी हाथ पांव फूल गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को परिजनों को सौंपकर घर भेज दिया।कस्बा समरेर निवासी विपिन ने अपनी पत्नी रेनू चार जून को महिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। पांच जून को दोनों बच्चों को एसएनसीयू में भर्ती करा दिया। लेकिन अस्पताल में न तो वेंटीलेटर है और न ही सीपैप की व्यवस्था है। शनिवार सुबह दोनों नवजातों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने स्टाफ पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत किया। बच्चों के शव परिजनों को सौंप कर घर भेज दिया।

ट्रंप और मस्क की दोस्ती जंग में तब्दील

» अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क एक दूसरे की कुंडली खोल रहे हैं

» आरोप प्रत्यारोप से अमेरिका की राजनीति गरमाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के बीच विवाद बढ़ने के बाद अब जुबानी जंग भी तेज हो गई गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय जहां दोनों एक-दूसरे की खूब तारीफ कर रहे थे तो अब दोनों खुलकर आमने-सामने आ गए हैं. ट्रंप ने शुक्रवार (6 जून 2025) को कहा कि एलन मस्क उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वह बातचीत के लिए तैयार नहीं है.

एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने एलन मस्क को लेकर कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है. इससे पहले खबर आई थी कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने विवाद को खत्म करने को लेकर ट्रंप और एलन मस्क के बीच 6 जून को मीटिंग रखी है. इसी मीटिंग के शेड्यूल को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एलन मस्क से मिलने से मना कर दिया.

ट्रंप ने गुरुवार (6 जून 2025) को दावा किया कि उन्होंने एलन मस्क की काफी मदद की, लेकिन अब वो मस्क से बहुत निराश हैं. उन्होंने दावा किया कि मस्क ईवी टैक्स इंसेटिव हटाए जाने से नाराज हैं. इस पर मस्क ने दावा किया कि इस बिल के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया गया और आधी रात को पास हुआ. मस्क ने यहां तक कह डाला कि मेरी ही वजह से ट्रंप चुनाव जीते. अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप की हार निश्चित थी.

ट्रंप और एलनमस्क के झगड़े को समझिए?

दोनों ने मिल के ताकत लगाई और सरकार बनाई। एक ने सम्हाला वाइट हाउस और दूसरे के लिए अलग से नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था डीओजीएफ (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी).. इस डिपार्टमेंट का काम था फालतू की सब्सिडी को घटाना अमेरिका के घाटे को कम करना। एलन मस्क ठहरा बिजनेस मैंन, फेक्ट और नंबर अच्छे से समझता है उसने करीब 300 बिलियन डॉलर के फालतू खर्चे और सब्सिडी कम कर दी। कुछ नए डिपार्टमेंट बनाए, कुछ नई पॉलिसी बनाई। इन्वेस्टर्स को ये देख कर बड़ी खुशी हुई। एक पॉजिटिविटी आ गई थी।

सब अच्छा चल रहा था..

लेकिन फिर दरार कहां से आई?

झगड़े की जड़ है नया बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल। और इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव आएगा टैक्स की कमी में।इसके अनुसार टिप के तौर पर कमाया पैसा या किसी कर्मचारी द्वारा ओवर टाइम किया गया पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। (ये तो

बेहतरीन बात हुई) अमेरिका में दो तरह के टैक्स होते हैं। 1. फैडरल (केंद्रीय) टैक्स.. इसकी सबसे ज्यादा अमीरों वाली दर 37त्न तक जाती है। 2. साल्ट, (स्टेट एंड लोकल टैक्स)... इसमें सेल्स, प्रॉपर्टी, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब आता है।

अमेरिकी नागरिक राज्य को जो भी टैक्स भरा है उसमें से 10,000 डॉलर तक की छूट आप केंद्र वाले टैक्स में ले सकते हो। लेकिन ट्रंप के नए बिल के बाद 10 हजार की बजाय अब आप 40 हजार तक की छूट ले सकते हैं।

इसके अलावा ट्रंप ने जो पिछले कार्यकाल में केंद्रीय कर कम किए थे उनकी अवधि खत्म होने वाली थी, उसे ट्रंप ने बढ़ा दिया। अमेरिका की जैसी हालत है उसके हिसाब से सरकार को टैक्स बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन ट्रंप के नए बिल के बाद कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा और बढ़ जाएगा।

एलन मस्क ने इसी बात को लेके बोला है कि ये बिल इकोनॉमी के लिए किल स्विच है। कि इसे लागू करते ही इकोनॉमी की लंका लग जाएगी।

इसके अलावा एलन मस्क के गुस्से की एक और वजह है।

अमेरिका में फिलहाल नए ईवी खरीदने पे 7,500 और पुराने ईवी खरीदने पर 4,000 डॉलर की छूट टैक्स में मिलती है। ये पैसा आप टैक्स भरते समय छूट ले सकते हैं। ट्रंप के नए बिल के बाद ये छूट ना सिर्फ खत्म हों जाएगीं बल्कि ईवी मेंटेन करने के लिए 250 डॉलर सालाना का मेंटीनेंस सरकार को देना होगा क्योंकि आप फ्यूल नहीं खरीद रहे जिससे सरकार को घाटा हो रहा है।

अमेरिका की सबसे बड़ी ईवी कंपनी ऐलन मस्क की ऋटेस्लाऋ है जिसे करीब 2 बिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना हैं।

टेस्ला के शेयर इस बकैती के दौरान 15त्न गिर चुके हैं।

एलन मस्क ने मोर्चा खोल दिया और बोला कि मेरे बिना ट्रंप कभी चुनाव नहीं जीतते।जब कि ट्रंप का कहना है वो मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते।

एसपियन फाइल्स (जिसमें कि कम उम्र की लड़कियों और लड़कों का यौन शोषण का मामला है) में ट्रंप का नाम है इस लिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। ट्रंप पर देशद्रोह का मुकदमा चला कर बाहर कर देना चाहिए। और वेंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, ट्रंप ने भी पलट के बोला है कि एलन मस्क पगला गया है।

बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में हो सकते हैं आम चुनाव

मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान, बेटपरी लोकतंत्र से देश में जंगलराज कायम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

ढाका/नई दिल्ली।भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में कराए जा सकते हैं। शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की. 84 वर्षीय यूनुस ने कहा, मैं देश के नागरिकों को यह घोषणा कर रहा हूं कि चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में किसी भी दिन होंगे. यह चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा. शेख हसीना को अगस्त 2024 में हुए एक छात्र-आंदोलन के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी थी,

जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी. बड़े पैमाने पर हुए उस विद्रोह ने 15 वर्षों से चल रहे अवामी लीग शासन को खत्म कर दिया था और देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी।

हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया,

जिसमें मुहम्मद यूनुस को स्थिरता बहाल करने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की तैयारी का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन तब से लेकर अब तक यूनुस की कार्यवाहक सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज से उठ रही मांगों को संतुलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अवामी लीग का पंजीकरण रद्द

बताया जा रहा है कि अवामी लीग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पार्टी का पंजीकरण इस महीने निलंबित कर दिया गया है, जिससे वह आगामी चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी. इस निर्णय की व्यापक आलोचना हो रही है.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने सोशल मीडिया के जरिए यूनुस पर ऋप्रतिशोध की राजनीतिऋ करने का आरोप लगाया है. वहीं, विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने चुनाव दिसंबर 2025 तक कराने की मांग दोहराई है. बीएनपी का कहना है कि बिना स्पष्ट समयसीमा के अंतरिम सरकार को समर्थन देना कठिन होता जा रहा है.